भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1996

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई के लिए एआई-आधारित साक्षरता और क्षमता निर्माण

1996. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित साक्षरता और डिजिटल क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है या प्रस्तावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएसएमई को एआई प्रशिक्षण, उपकरण और सलाहकार सहायता प्रदान करने के लिए उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों या प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के साथ योजनाओं या भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा कृत्रिम प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने और लागत, कौशल में अंतर और अवसंरचना तक पहुंच सहित पेश आ रही चुनौतियों के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कृत्रिम उद्यम द्वारा संचालित समाधानों तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ): सरकार एमएसएमई में यांत्रिक बुद्धिमता (एआई) के अंगीकरण के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न उपाय कर रही है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 10,371.92 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ दिनांक 7 मार्च, 2024 को अनुमोदित इंडियाएआई मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। मिशन में सात स्तंभ हैं:- इंडियाएआई कम्प्यूट क्षमता, इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर, इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडियाएआई एप्लीकेशन विकास पहल, इंडियाएआई फ्यूचर स्किल्स, इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सेफ एंड ट्रस्टेड एआई जिनका लक्ष्य समाज के सभी स्तरों पर एआई के लाभों का लोकतंत्रीकरण करना, एआई नवाचार पारितंत्र को मजबूत करना और सामाजिक रूप से प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, जिसमें सभी सेक्टर में एआई के अंगीकरण की सुविधा प्रदान करना शामिल है। मिशन का लक्ष्य एमएसएमई सहित समाज के सभी स्तरों पर एआई के लाभों का लोकतंत्रीकरण करना है ताकि उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।

सरकार उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से एमएसएमई के बीच डिजिटल अंगीकरण की सीमा का समय-समय पर आकलन करती है। नीति आयोग का आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) भी सरकारी अंत:क्षेपों के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य करता है।

***